नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 108
दि. 20.01.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

2030 तक उच्च मध्य आय देश बनेगा भारत, प्रति व्यक्ति आय में 33 प्रतिशत से अधिक उछाल की उम्मीद

(जीएनएस)। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले चार वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय में 33 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है और वर्ष 2030 तक भारत उच्च मध्य आय श्रेणी वाले देशों के समूह में शामिल हो सकता है। यह आकलन केवल आंकड़ों का अनुमान नहीं है, बल्कि बीते वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा दिखाई गई मजबूती और सुधारों का स्वाभाविक परिणाम माना जा रहा है। यदि यही रफ्तार बनी रही तो वर्ष 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2009 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1110 डॉलर थी, जो 2019 में बढ़कर 2070 डॉलर हो गई। अनुमान है कि 2026 तक यह आंकड़ा 3108 डॉलर तक पहुंच जाएगा और 2030 तक 4276 डॉलर के स्तर को छू सकता है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर देश के जीवन स्तर, खपत क्षमता और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालेगी। अधिक आय का अर्थ है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं तक आम नागरिक की पहुंच में विस्तार।

भारतीय अर्थव्यवस्था का सफर अपने आप में अद्भुत रहा है। आजादी के बाद पहले एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में देश को लगभग छह दशक लगे, लेकिन इसके बाद विकास की गति कई गुना तेज हो गई। 2014 में भारत दो ट्रिलियन डॉलर, 2021 में तीन ट्रिलियन डॉलर और 2025 में चार ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया। अब लक्ष्य 2027-28 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की मंजिल हासिल करने का है। यह परिवर्तन बताता है कि सुधारों, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे में निवेश ने देश की आर्थिक दिशा पूरी तरह बदल दी है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार यदि वर्तमान सुधारों की लय बरकरार रही तो 2047 तक, जब भारत आजादी के सौ वर्ष पूरे करेगा, देश उच्च आय वाली श्रेणी में प्रवेश कर सकता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति आय को लगभग 12.63 लाख रुपये या 13,936 डॉलर के स्तर तक पहुंचाना होगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 7.5 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर आवश्यक होगी। बीते दो दशकों का औसत देखें तो यह दर 8.3 प्रतिशत रही है, इसलिए लक्ष्य असंभव नहीं दिखता।

देश की इस आर्थिक छलांग के पीछे कई कारक काम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और बुनियादी ढांचे में हो रहा भारी निवेश विकास की नई नींव रख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, इंटरनेट और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। सेवा क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र भी धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है और वैश्विक कंपनियां भारत को उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में देखने लगी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च आय की श्रेणी में पहुंचने के लिए भारत को विनिर्माण और औद्योगिक निवेश पर विशेष ध्यान देना होगा। केवल सेवा क्षेत्र के भरोसे विकसित राष्ट्र का सपना पूरा नहीं हो सकता। रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार, निर्यात वृद्धि और श्रम उत्पादकता में सुधार इस यात्रा के अनिवार्य स्तंभ होंगे। यदि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख केंद्र बन जाता है तो आय वृद्धि की गति और तेज हो सकती है। हालांकि राह पूरी तरह आसान नहीं है। वैश्विक मानकों के अनुसार उच्च आय की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है। 2047 तक यह सीमा 13,936 डॉलर से बढ़कर लगभग 18,000 डॉलर तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को अगले दो दशकों तक लगभग 8.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी। यह चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन सही नीतिगत फैसलों और स्थिर राजनीतिक इच्छाशक्ति से इसे हासिल किया जा सकता है।

विशेषज्ञ इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि केवल सकल घरेलू उत्पाद का बढ़ना पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि इस विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्थिक असमानता को कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा कौशल विकास पर निवेश, इन सबके बिना उच्च आय देश का सपना अधूरा रहेगा। भारत की विशाल युवा आबादी एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसे उत्पादक श्रमशक्ति में बदलना सबसे अहम कार्य होगा।

कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीते वर्षों में मिले संकेत बताते हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय में प्रस्तावित वृद्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन में वास्तविक बदलाव का संकेत है। यदि नीतियों में निरंतरता रही, निवेश का माहौल मजबूत बना और वैश्विक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया गया, तो 2030 तक उच्च मध्य आय देश और 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होना दूर की बात नहीं रहेगी।

बस्तर में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, 4 महिला समेत 6 इनामी माओवादी ढेर, कुल 27 लाख का था इनाम

(जीएनएस)। बस्तर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार महिला समेत छह इनामी माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों पर कुल 27 लाख रुपये का इनाम घोषित था और ये सभी लंबे समय से कई गंभीर वारदातों में शामिल रहे थे। इस मुठभेड़ को बस्तर संभाग में माओवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक यह ऑपरेशन दो दिनों तक चला और इसमें डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ तथा कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि 17 जनवरी को सुरक्षा एजेंसियों को नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की गोपनीय सूचना मिली थी। इसके बाद तुरंत संयुक्त टीमों को सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। जवान जैसे ही चिन्हित क्षेत्र में पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। यह मुठभेड़ 17 जनवरी की शाम से शुरू होकर 18 जनवरी तक रुक-रुक कर चलती रही।

अधिकारी ने बताया कि शनिवार को चार और रविवार को दो माओवादियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज और खूंखार माओवादी नेता दिलीप बेड़जा भी शामिल है, जिस पर अकेले 8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। दिलीप पर हत्या, लूट, आगजनी और पुलिस दल पर हमले जैसे 135 से अधिक मामले दर्ज थे। वह बीजापुर और बस्तर क्षेत्र में कई बड़ी घटनाओं का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता था।

अन्य मारे गए माओवादियों में माड़वी कोसा, पालो पोड़ियम और लक्खी मड़कम शामिल हैं, जिन पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसके अलावा जुगलो बंजाम और राधा मेट्टा नामक नक्सलियों पर दो-दो लाख रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार ये सभी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य थे और इलाके में ग्रामीणों को डराने-धमकाने, विकास कार्यों में बाधा डालने तथा सुरक्षा बलों पर हमलों में शामिल रहे थे। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षाबलों को दो एके-47 रायफल, तीन मैगजीन, 32 राउंड गोलियां, एक इंसास रायफल, दो मैगजीन और 30 राउंड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा दो श्री नॉट श्री रायफल, एक कार्बाइन, बीजीएल लॉन्चर और आठ बीजीएल सेल भी बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलना इस बात का संकेत है कि माओवादी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीजापुर जिला लंबे समय से माओवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों की रणनीति और स्थानीय खुफिया तंत्र मजबूत होने से नक्सलियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2025 में अब तक बीजापुर क्षेत्र में कुल 163 माओवादी मारे जा चुके हैं, जबकि इस वर्ष की शुरुआत में ही आठ नक्सली ढेर हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि सुरक्षा बलों का अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। इलाके के लोगों का कहना है कि माओवादियों की मौजूदगी के कारण वर्षों से विकास कार्य ठप पड़े थे। सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही थीं। अब नक्सलियों के कमजोर पड़ने से लोगों में सुरक्षा की भावना लौटने लगी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि क्षेत्र में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दिलीप बेड़जा जैसे शीर्ष कमांडर के मारे जाने से नेशनल पार्क एरिया कमेटी की कमर टूट गई है। संगठन को नया नेतृत्व खड़ा करने में लंबा समय लगेगा। हालांकि सुरक्षाबलों ने चेतावनी दी है कि माओवादी बौखलाहट में किसी कायराना हरकत को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने इस सफलता के लिए ऑपरेशन में शामिल सभी जवानों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में शांति और विकास ही सरकार की प्राथमिकता है और हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग हथियार छोड़कर समाज के साथ जुड़ेंगे, उन्हें रोजगार और पुनर्वास के पूरे अवसर दिए जाएंगे।

आरएसएस और भाजपा देश को कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती हैं: राहुल गांधी

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दोनों संगठन देश की जनता को चुप कराकर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं ताकि भारत को कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों के हाथों सौंपा जा सके। केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ऐसा कभी होने नहीं देगी और संविधान की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेगी।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आज देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें लोगों से सवाल पूछने का अधिकार छीना जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि आम नागरिक चुपचाप उनकी हर बात स्वीकार कर लें। उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर कुछ बड़े व्यापारिक घरानों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास इसके ठीक विपरीत रहा है। कांग्रेस ने हमेशा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, पंचायतों और स्थानीय निकायों को मजबूत किया और लोगों को फैसलों में भागीदार बनाया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान बचाने का अर्थ केवल किताब को बचाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सत्ता और निर्णय लेने का अधिकार देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। भाजपा और आरएसएस सत्ता को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित करना चाहती हैं, जबकि कांग्रेस गांव, कस्बे और शहरों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में विश्वास रखती है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर इस सच्चाई को बताएं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता और अभिव्यक्ति की आजादी में है। जिस दिन लोग डर के कारण बोलना बंद कर देंगे, उस दिन देश की आत्मा कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी महान राष्ट्र तब बनता है जब उसके नागरिक खुलकर अपने विचार रखते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। चुप रहने की संस्कृति दरअसल लालच और डर से पैदा होती है, जो समाज को भीतर से खोखला कर देती है।

कोच्चि में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. एम लीलावती को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रियदर्शिनी साहित्य पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने साहित्य और संस्कृति के महत्व पर बोलते हुए कहा कि लेखक और विचारक समाज की अंतरात्मा होते हैं। वे सत्ता से सवाल पूछते हैं और जनता को सही दिशा दिखाते हैं। यदि लेखकों की आवाज दबा दी जाए तो लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान के मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि देश की संस्थाओं, न्यायपालिका, मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार इन संस्थाओं पर लगातार दबाव बना रही है और विरोध की हर आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में कांग्रेस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिला जब महापंचायत के बीच एक छोटा बच्चा मंच पर आकर राहुल गांधी के साथ तस्वीर खिंचवाने लगा। राहुल ने मुस्कुराते हुए बच्चे को अपने पास बुलाया, उसके साथ सेल्फी ली और उसे चॉकलेट भी दी। इस घटना ने माहौल को हल्का कर दिया और कार्यकर्ताओं ने तालियों से राहुल का स्वागत किया।

राहुल गांधी ने अंत में कहा कि कांग्रेस का संघर्ष किसी एक व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ है जो देश की संपत्ति और संसाधनों को कुछ लोगों के हवाले करना चाहती है। उन्होंने भरोसा जताया कि केरल सहित पूरे देश की जनता इस सच्चाई को समझ रही है और आने वाले समय में लोकतंत्र तथा संविधान की जीत होगी। उनके इस भाषण ने केरल के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया और कार्यक्रम एकजुटता के संकल्प के साथ समाप्त हुआ।

लेह में 5.7 तीव्रता के भूकंप से दहला लद्दाख, कश्मीर घाटी तक महसूस हुए झटके

(जीएनएस)। लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का शांत पहाड़ी इलाका सोमवार को उस समय अचानक दहल उठा, जब सुबह 11 बजकर 51 मिनट पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.7 मापी गई। झटके इतने मजबूत थे कि लेह और आसपास के क्षेत्रों में लोग घबराकर घरों, दुकानों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में भी कंपन महसूस किया गया, जिससे कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भूकंप के समय इमारतें हिलती हुई महसूस हुईं और दरवाजे-खिड़कियां तेज आवाज के साथ कांपने लगीं। लेह जैसे ठंडे और अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में इस तरह का तेज भूकंप लंबे समय बाद महसूस किया गया, इसलिए लोगों में स्वाभाविक रूप से डर देखा गया। बाजारों में मौजूद लोग खुले मैदानों की ओर भागते नजर आए, वहीं स्कूलों में बच्चों को सावधानी के तौर पर कक्षाओं से बाहर निकाल लिया गया।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि भूकंप का केंद्र 36.71 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.32 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इसका केंद्र जमीन से लगभग 171 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया, जो अपेक्षाकृत काफी नीचे माना जाता है। इतनी अधिक गहराई के बावजूद झटकों की तीव्रता इतनी थी कि लेह के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भी इसका असर महसूस हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के लगातार टकराव के कारण यहां ऊर्जा जमा होती रहती है, जो समय-समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। लद्दाख और कश्मीर उसी सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं, जिसे वैज्ञानिक 'हाई सिस्मिक जोन' की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए इस इलाके में मध्यम से तेज तीव्रता के भूकंप आना असामान्य घटना नहीं है।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार फिलहाल कहीं से भी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। जिला प्रशासन ने पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। अस्पतालों में भी एहतियात के तौर पर विशेष तैयारियां की गईं, हालांकि दोपहर तक किसी घायल के पहुंचने की खबर नहीं थी।

भूकंप के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए। लेह, कारगिल, श्रीनगर और बारामूला से कई लोगों ने बताया कि झटके करीब 10 से 15 सेकंड तक महसूस होते रहे। कुछ लोगों ने इसे अब तक का सबसे तेज कंपन बताया, जबकि कुछ ने कहा कि गहराई अधिक होने के कारण नुकसान कम हुआ। भूकंप विज्ञानियों के अनुसार 5.7 तीव्रता का भूकंप मध्यम श्रेणी में आता है, लेकिन यदि इसका केंद्र जमीन की सतह के पास होता तो नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। 171 किलोमीटर की गहराई ने इसकी विनाशक क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया। फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने का खतरा बना रहता है, इसलिए प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।

लेह के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों के मौसम के कारण पहले से ही जनजीवन चुनौतीपूर्ण रहता है। ऐसे में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देती है। कई गांव ऐसे हैं जहां संचार साधन सीमित हैं, इसलिए वहां की वास्तविक स्थिति जानने में समय लग सकता है। प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों से रिपोर्ट जुटाने के लिए विशेष दल रवाना किए हैं। कश्मीर घाटी में भी झटकों के बाद लोग सहम गए। श्रीनगर के लाल चौक, बडगाम और अनंतनाग में लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति कुछ देर के लिए बाधित हुई, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में भी सतर्कता बरती गई और इमारतों की जांच कराई गई। मौसम और भूगर्भ विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में आफ्टरशॉक यानी भूकंप के बाद हल्के झटके आने की संभावना बनी रहती है।

कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश सरकार से मांगा तुरंत फैसला

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी में हो रही देरी अस्वीकार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिश पर समय रहते निर्णय ले। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महीनों से फाइल लंबित रखना न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने 19 अगस्त 2025 को ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और तब से लगभग पांच महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभियोजन की मंजूरी पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अदालत ने टिप्पणी की कि कानून स्पष्ट रूप से राज्य पर यह दायित्व डालता है कि ऐसे मामलों में बिना अनावश्यक देरी के फैसला लिया जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की सीलबंद रिपोर्ट खोली और पाया कि जांच एजेंसी ने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया उनके बयान को आपत्तिजनक और सैन्य अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है। अदालत ने कहा कि जब जांच एजेंसी अपना काम पूरा कर चुकी है, तो सरकार का दायित्व है कि वह आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता साफ करे।

यह मामला उस समय का है जब भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ी आधिकारिक जानकारी मीडिया को दे रही थीं। उसी दौरान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कुंवर विजय शाह ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, उन्हें सबक सिखाने के लिए हमने उन्हीं की एक बहन को भेजा है। इस बयान को महिला अधिकारी और सेना के मनोबल पर हमला माना गया और देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई।

विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया था। एसआईटी ने गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी, लेकिन उसके बाद से मामला मंजूरी के स्तर पर अटका रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से दो टूक कहा कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अदालत ने निर्देश दिया कि सरकार जल्द से जल्द अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय लेकर अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करे। पीठ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से संवैधानिक मर्यादा की अपेक्षा की जाती है और ऐसे संवेदनशील मामलों में ढिलाई का संदेश गलत जाता है।

कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े इस प्रकरण को सेना और महिला सम्मान से जुड़े गंभीर मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को अब जल्द कोई ठोस कदम उठाना ही होगा, अन्यथा उसे अदालत की और कठोर टिप्पणी का सामना करना पड़ सकता है।

संपादकीय

रोजगार सृजन से संभव विकसित भारत का

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने देश में बेरोजगारी की बढ़ती स्थिति को लेकर गंभीर संकेत दिए हैं। दिसंबर माह में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.8 प्रतिशत तक पहुंच जाना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की अधूरी उम्मीदों की कहानी है। भारत को विश्व में युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारी बड़ी आबादी काम करने की आयु वर्ग में है। यही युवा शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, परंतु जब यही वर्ग रोजगार के लिए भटकने लगे तो विकास की पूरी दिशा पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यह समय गहन आत्ममंथन का है कि हम इस विशाल मानव संसाधन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट का एक और चिंताजनक पहलू शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी के बीच का अंतर है। सामान्य धारणा रही है कि शहर अवसरों के केंद्र होते हैं, परंतु वास्तविकता इससे अलग दिखाई दे रही है। शहरी क्षेत्रों में पंद्रह वर्ष से अधिक आयु के युवाओं में बेरोजगारी 6.7 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 3.9 प्रतिशत पर स्थिर रही। इसका अर्थ है कि शहरों में उद्योग और सेवा क्षेत्र उतनी तेजी से रोजगार नहीं बना पा रहे, जितनी तेजी से युवा वहां पहुंच रहे हैं। बढ़ता शहरीकरण, सीमित औद्योगिक विस्तार और महंगी जीवनशैली ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का वास्तविक पैमाना केवल विकास दर नहीं हो सकती। यदि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा हो लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हों, तो वह विकास अधूरा माना जाएगा। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल पूंजी निर्माण नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना भी है। जब युवाओं के हाथ खाली रहते हैं, तब बाजार में मांग कमजोर पड़ती है, सामाजिक असंतोष बढ़ता है और अपराध की प्रवृत्तियां भी जन्म लेती हैं। इसलिए रोजगार सृजन को आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु बनाना अनिवार्य है।

भारत में रोजगार का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है। छोटे उद्योग, दुकानें, सेवा कार्य और कृषि आधारित गतिविधियां करोड़ों लोगों को आजीविका देती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह क्षेत्र लगातार दबाव में है। महंगी पूंजी, जटिल कर प्रणाली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और वैश्विक मंदी के असर से छोटे उद्यम कमजोर हुए हैं। जब ये इकाइयां बंद होती हैं या सिकुड़ती हैं, तो सबसे पहले नौकरियां ही खत्म होती हैं। संगठित क्षेत्र भी सीमित भर्तियां कर रहा है, जिससे समस्या और विकट हो गई है।

तकनीकी परिवर्तन ने भी रोजगार के स्वरूप को तेजी से बदल दिया है। कृत्रिम मेधा, स्वचालन और डिजिटल माध्यमों ने उत्पादन क्षमता तो बढ़ाई है, परंतु मानव श्रम की आवश्यकता कम कर दी है। बैंकिंग, विनिर्माण, खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में मशीनें और सॉफ्टवेयर मनुष्य का स्थान ले रहे हैं। यह परिवर्तन अनिवार्य है, परंतु इसके साथ युवाओं को तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। यदि शिक्षा और प्रशिक्षण पुराने ढर्रे पर चलते रहे तो नई पीढ़ी इस दौड़ में पीछे छूट जाएगी।

सरकार ने कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। लेकिन जमीनी अनुभव बताता है कि कई प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल प्रमाणपत्र बांटने तक सीमित रह गए हैं। उद्योगों की वास्तविक जरूरतें कुछ और हैं, जबकि प्रशिक्षण कुछ और दिया जा रहा है। जब तक पाठ्यक्रम और बाजार की मांग के बीच सीधा संबंध नहीं बनेगा, तब तक इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की घटती संख्या भी युवाओं की निराशा का बड़ा कारण है। पहले सरकारी सेवा को स्थिर भविष्य का प्रतीक माना जाता था, परंतु अब भर्तियां सीमित होती जा रही हैं। परीक्षा प्रक्रिया में देरी, परिणामों की अनिश्चितता और पारदर्शिता पर उठते सवाल युवाओं का भरोसा कमजोर करते हैं। लाखों शिक्षित युवक वर्षो तक तैयारी करते रहते हैं और अंत में कुछ गिने चुने पदों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। इससे समय और ऊर्जा दोनों का नुकसान होता है। शिक्षा व्यवस्था की भूमिका भी इस संकट में महत्वपूर्ण है। हमारे अधिकांश विश्वविद्यालय और कॉलेज अभी भी पारंपरिक पाठ्यक्रमों पर टिके हैं। व्यावहारिक कौशल, नवाचार और उद्यमिता को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। परिणाम यह है कि डिग्रीधारी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, परंतु रोजगार योग्य युवाओं की संख्या कम है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि जीवन यापन के लिए सक्षम बनाना होना चाहिए।

बेरोजगारी का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी होता है। काम न मिलने से युवाओं में हताशा, तनाव और आत्मविश्वास की कमी पैदा होती है। परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और समाज में असमानता गहरी होती है। जब एक बड़ा वर्ग उपेक्षित महसूस करता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी दबाव पड़ता है। इसलिए रोजगार का प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है।

लोकतंत्र में कानून ही लोक की अंतिम उम्मीद

> वर्ष के अंत में न्यायपालिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार और अरावली में खनन आवंटन पर पर्यावरण को सर्वोपरि मानकर विचार करने से जनता आश्वस्त हुई है कि भारतीय लोकतंत्र में अन्याय के प्रतिकार के मार्ग सदैव खुले रहते हैं।

भारत की न्यायपालिका की परंपरा अत्यंत गरिमापूर्ण रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए उसने हाल के दिनों में भी वैसा ही आचरण किया है, जैसा एक स्वतंत्र न्यायपालिका से अपेक्षित होता है। किसी अधिनायकवादी देश में यह कल्पना भी कठिन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करे या निचली अदालत के आदेश को गलत मानकर उसमें संशोधन करे। भारत में यह संभव हुआ है, जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। यहां देर-सबेर जनता की आवाज सुनी जाती है। सरकारी फैसले, जो लोगों को पीड़ित, क्रुद्ध या उन्हें आक्रोशित करते हैं, तो सरकार भी जनभावनाओं के अनुरूप अपने निर्णय बदलती है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्ची पहचान और सामूहिक प्रगति का मार्ग है।

हम यहां किसान आंदोलन की चर्चा नहीं करेंगे, जिसके बारे में सरकार ने उनके लंबे धरनों के बाद किए गए फैसले वापस ले लिए। हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात भी नहीं करेंगे, जिसके संबंध में केंद्र ने पंजाबियों की भावनाओं को समझते हुए अपना फैसला बदल दिया। ऐसे में पंजाब यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह पंजाब की शान बनी रही।

नवीनतम फैसलों की चर्चा करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वत शृंखला में खनन से संबंधित अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार का निर्णय उल्लेखनीय है। न्यायालय को यह आशंका हुई कि खनन आवंटन और अरावली के संरक्षण के बीच संतुलन न बिगड़ जाए, इसलिए विशेषज्ञों से पुनः विचार कर नया फैसला देने का निर्णय लिया गया। यह न्यायपालिका की पर्यावरणीय संवेदनशीलता और लोचशीलता को दर्शाता है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य आदेश ने भारतीय लोकतंत्र में सबकी बात सुने जाने की गरिमा को पुनः स्थापित किया। यह मामला उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर से जुड़ा है, जिसकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वर्ष 2017 के उन्नाव कांड में पीड़िता और उसके परिवार पर हुए अमानवीय अत्याचार, धमकियां और हिंसा ने पूरे देश को झकझोर दिया था। पीड़िता और उसके पिता ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई। इसके पहले, बाहुबली ने लालच देकर उन्हें लोकलाज का भय दिखाकर चुप रहने के लिए दबाव डाला। इसके बाद पीड़िता के पिता को कुछ मामलों में फंसाकर हिरासत में रखा गया, उनकी मारपीट करवाई गई, और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस बाहुबली ने 23 दिसंबर, 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत प्राप्त कर ली थी। दलील दी कि वह एक जनसेवक है और पहले ही इस मामले में पांच साल की सजा भोग चुका है। पीड़िता के भय का अंत नहीं हुआ, क्योंकि बाहुबली रिहा हो गया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं और पीड़ित के भय का अंत करना न्याय की मूल शर्त है।

देशभर में इस फैसले का स्वागत किया गया, क्योंकि बाहुबली के सामने निर्बल पीड़ितों की आवाज सुनी गई। ऐसी घटनाएं केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव हैं। बार-बार यह सिद्ध हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र अंततः अपनी गरिमा स्थापित करता है। यहाँ विपक्ष की आवाज सुनी जाती है और पीड़ितों व वंचितों के हितों पर ध्यान दिया जाता है। जातिगत जनगणना इसका उदाहरण है। लंबे समय से विपक्ष इसकी मांग कर रहा था, क्योंकि 2011 के बाद यह नहीं हुई थी। 2026 में प्रस्तावित जनगणना से पहले ही केंद्र सरकार ने स्वयं जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया।

भारतीय समाज एक खुला समाज है। जब भी कोई त्रुटि या प्रवंचना सामने आती है, सरकार—चाहे कोई भी हो—उसका संज्ञान लेकर निर्णय बदलने से नहीं हिचकती। सामान्यतः न्यायपालिका के निर्णय अंतिम माने जाते हैं, किंतु जहां आवश्यक हुआ, वहां सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल बाहुबली की सजा निलंबन पर रोक लगाई, बल्कि अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करने का साहस भी दिखाया। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया गया। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हाल के चुनावों में सत्ता और विपक्ष दोनों एकमत दिखाई दिए। वर्ष के अंत में न्यायपालिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार और अरावली में खनन आवंटन पर पर्यावरण को सर्वोपरि मानकर विचार करने से जनता आश्वस्त हुई है कि भारतीय लोकतंत्र में अन्याय के प्रतिकार के मार्ग सदैव खुले रहते हैं।

प्रेरणा

योग्यता की कसौटी पर मंत्र

एक प्राचीन राज्य की कथा है, जहां का राजा जितना पराक्रमी था उतना ही जिज्ञासु भी। उसे युद्ध और शासन के साथ साथ ज्ञान की सूक्ष्म बातों में गहरी रुचि थी। उसके दरबार में एक अनुभवी मंत्री था जो राजकार्य के साथ आध्यात्मिक साधना भी करता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर मंत्र-जप करता, फिर शांत मन से राज्य के कार्यों में लग जाता। राजा यह सब देखता तो उसके मन में प्रश्न उठता कि क्या सचमुच मंत्र-जप से कोई विशेष शक्ति प्राप्त होती है और क्या यह शक्ति हर व्यक्ति को समान रूप से मिलती है।

एक दिन राजा ने अवसर देखकर मंत्री से यही बात पूछ ली। मंत्री ने संक्षिप्त उत्तर दिया कि मंत्र का प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं होता, यह साधक की पात्रता पर निर्भर करता है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने विस्तार से समझाने का आग्रह किया। मंत्री जानता था कि यह विषय केवल तर्क से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए उसने कहा कि समय आने पर उदाहरण सहित समझाऊंगा।

कुछ दिनों बाद मंत्री ने एक योजना बनाई। वह राजा को महल के एक शांत कक्ष में ले गया और पास के गांव से एक साधारण बालक को बुलवाया। बालक सीधा-सादा था, उसे राजसी वातावरण का कोई ज्ञान नहीं था। मंत्री ने बालक से कहा कि यह व्यक्ति मुझे रोज परेशान करता है, तुम इसे एक थप्पड़ मार दो। बालक ने यह सुनकर संकोच से मंत्री की ओर देखा और आदेश का पालन नहीं किया। उसे लगा कि यह अनुचित काम है।

राजा यह दृश्य देख रहा था। तभी उसने स्वयं बालक को आदेश दिया कि मंत्री को थप्पड़ मारो। इस बार बालक ने बिना देर किए आज्ञा का पालन कर दिया। मंत्री शांत खड़ा रहा, मानो पहले से ही इस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि एक ही बालक ने दो आदेशों पर इतना भिन्न व्यवहार क्यों किया।

तब मंत्री ने कहा, महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार इस बालक ने केवल उसी का आदेश माना जिसे वह वास्तविक अधिकारी समझता था, उसी प्रकार मंत्र-शक्ति भी केवल योग्य व्यक्ति की पुकार सुनती है। मंत्र कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं कि शब्द बोले और फल मिल गया। वह चेतना की जीवित धारा है, जो साधक के मन और आचरण को परखती है।

मंत्री ने आगे समझाया कि संसार की हर शक्ति नियमों से बंधी है। जैसे अग्नि केवल सूखे ईंधन में ही प्रज्वलित होती है, उसी तरह मंत्र भी शुद्ध हृदय में ही फलता है। यदि मन लोभ, क्रोध और अहंकार से भरा है तो मंत्र-जप केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। पर जहां करुणा, सत्य और संयम है, वहां वही मंत्र वरदान का रूप ले लेता है। राजा ने पूछा कि फिर इतने लोग वर्षों जप करके भी खाली हाथ क्यों रहते हैं। मंत्री ने कहा कि वे बाहरी क्रिया को सब कुछ मान लेते हैं। असली साधना भीतर के परिवर्तन की यात्रा है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं बदलता, वह कितने भी मंत्र बोले, उसका जीवन नहीं बदलता। मंत्र बीज की तरह है, पर बीज तभी अंकुरित होता है जब भूमि उपजाऊ हो।

मंत्री की बातों से राजा के मन में नया दृष्टिकोण पैदा हुआ। उसने समझा कि वह अब तक मंत्र को चमत्कार समझता था, जबकि वह तो जीवन को शुद्ध करने का माध्यम है। मंत्री ने बताया कि पात्रता रोज के आचरण से बनती है—सत्य बोलना, अन्याय से दूर रहना, दूसरों की पीड़ा समझना और मन को अनुशासित रखना। बिना इन गुणों के मंत्र केवल औपचारिकता रह जाता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या मंत्र किसी अयोग्य व्यक्ति को कभी लाभ नहीं देता। मंत्री ने कहा कि लाभ मिल भी जाए तो टिकता नहीं, क्योंकि आधार कमजोर होता है। जैसे कच्ची दीवार पर रंग ठहर नहीं पाता, वैसे ही अशुद्ध मन में शक्ति स्थिर नहीं रहती। इसलिए पहले स्वयं को गढ़ना पड़ता है, तभी वरदान स्थायी बनता है। उस दिन राजा के भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। उसने अनुभव किया कि सत्ता और शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण योग्यता है। उसने देखा कि दरबार में अनेक लोग पद तो चाहते हैं पर उत्तरदायित्व नहीं, सम्मान चाहते हैं पर सेवा नहीं। यही कारण है कि समाज में असंतुलन पैदा होता है। यदि हर व्यक्ति पहले पात्र बनने का प्रयास करे तो आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएं। मंत्री ने अंत में कहा कि मंत्र-शक्ति किसी का पक्ष नहीं लेती, वह केवल धर्म का पक्ष लेती है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, मंत्र उसकी सहायता करता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे नदी सबको जल देती है, पर पात्र वही भर पाता है जो झुकना जानता है। अहंकार से भरा घड़ा खाली ही रह जाता है।

राजा ने इस शिक्षा को जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपने व्यवहार में विनम्रता और न्याय को स्थान दिया। प्रजा के दुखों को सुनने लगा और निर्णयों में करुणा का भाव आने लगा। धीरे-धीरे पूरे राज्य में यह चर्चा फैल गई कि शक्ति मांगने से पहले स्वयं को योग्य बनाना चाहिए।

वर्षों बाद वही बालक बड़ा होकर राज्य का विश्वस्त कर्मचारी बना। वह अक्सर लोगों से कहता कि उस दिन उसने जाना कि आदेश वही प्रभावी होते हैं जिनके पीछे सच्चा अधिकार हो। मंत्र भी ऐसा ही अधिकार चाहता है—आचरण का, सत्य का और करुणा का।

यह कथा केवल एक राजा और मंत्री की नहीं, हर मनुष्य की है। हम सब किसी न किसी शक्ति की कामना करते हैं, पर भूल जाते हैं कि पहले स्वयं को उसके योग्य बनाना होता है। सृष्टि का नियम स्पष्ट है—पात्रता पहले, प्राप्ति बाद में। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए साधना बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। तब मंत्र केवल शब्द नहीं रहते, वे जीवन को उजाला देने वाली ज्योति बन जाते हैं और मनुष्य भीतर से रूपांतरित हो उठता है।

घुसपैठ पर निर्णायक नीति की जरूरत

प्रधानमंत्री द्वारा एक बार फिर अवैध घुसपैठ के प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाना यह दर्शाता है कि समस्या अब केवल सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। लाल किले की प्राचीर से लेकर चुनावी सभाओं तक इस विषय को बार-बार उठाया गया है और समाधान की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है, परंतु जमीनी स्तर पर ठोस और स्थायी परिणाम अभी भी अपेक्षित दिखाई नहीं देते। प्रश्न स्वाभाविक है कि इतने वर्षों के राजनीतिक संकल्प के बाद भी यह समस्या निर्णायक मोड़ तक क्यों नहीं पहुंच सकी।

भारत जैसे विशाल और लोकतांत्रिक देश में अवैध घुसपैठ केवल सीमा सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि बहुआयामी राष्ट्रीय संकट है। इसका प्रभाव जनसांख्यिकीय संरचना पर पड़ता है, स्थानीय रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं, सरकारी योजनाओं पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है और सामाजिक ताने-बाने में अविश्वास की भावना जन्म लेती है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और पूर्वोत्तर के अनेक जिलों में जनसंख्या संतुलन के बदलते समीकरण इस खतरे की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। कई क्षेत्रों में मूल निवासियों को यह महसूस होने लगा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आजीविका दोनों असुरक्षित हो रही हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अवैध घुसपैठ केवल मानवीय प्रवाह तक सीमित नहीं रहती, इसके साथ संगठित अपराध, नकली मुद्रा, नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकी नेटवर्क की आशंकाएं भी जुड़ जाती हैं। फर्जी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की शिकायतें लोकतंत्र की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। यदि किसी देश की मतदाता सूची ही संदिग्ध हो जाए तो नीति निर्माण और जनप्रतिनिधित्व की पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है।

एनडीए सरकार को केंद्र में ग्यारह वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, इसलिए जनता का यह पूछना उचित है कि घुसपैठ रोकने के लिए अब तक निर्णायक ढांचा क्यों नहीं बन पाया। विपक्ष आरोप लगाता है कि इस मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए जीवित रखा जाता है, जबकि सरकार का दावा है कि सीमा सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं हो सकती है, परंतु इतना स्पष्ट है कि परिणाम उतने प्रभावी नहीं दिखते जितनी अपेक्षा की गई थी।

आधिकारिक आंकड़ों में भी विरोधाभास दिखाई देता है। पूर्ववर्ती सरकार के काल में हजारों अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के दावे किए गए थे, जबकि बाद के वर्षों में यह संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई। 2019 के बाद के वर्षों का विश्वसनीय और अद्यतन आंकड़ा सार्वजनिक न होना नीति की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। जब तक वास्तविक संख्या, प्रवेश मार्ग और राज्यों में इनके वितरण का प्रमाणिक विवरण सामने नहीं आएगा, तब तक किसी भी कार्रवाई की योजना अधूरी ही रहेगी।

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का व्यापक अभ्यास हुआ, करोड़ों रुपये खर्च हुए और समाज में गहरी बेचैनी भी फैली, परंतु अंतिम सूची आने के बाद अपेक्षित कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। लाखों लोग न तो स्पष्ट रूप से नागरिक घोषित हुए, न ही अवैध प्रवासी सिद्ध हुए। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक विफलता का संकेत है, बल्कि मानवीय संकट भी पैदा करती है। ऐसी अधूरी प्रक्रियाएं समस्या सुलझाने के बजाय उसे और उलझा देती हैं।

घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केवल राज्यों पर डाल देना उचित नहीं होगा। यह विषय गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, विदेश मंत्रालय और कूटनीतिक तंत्र के समन्वित प्रयास से ही सुलझ सकता है। पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी संवाद, प्रत्यर्पण समझौते और सीमा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकें अनिवार्य हैं। यदि अंतर-मंत्रालयी तालमेल कमजोर रहेगा तो कोई भी नीति कागजों तक सीमित रह जाएगी।

कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कदम उठाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में 'डिटेक्ट, डिलीट, डीपोर्ट' जैसी नीति की चर्चा रही, बिहार में संदिग्ध लोगों को नोटिस देने की प्रक्रिया अपनाई गई, परंतु पश्चिम बंगाल और असम जैसे सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में समान कठोरता क्यों नहीं दिखती, यह बड़ा प्रश्न है। क्या संघीय राजनीति, स्थानीय वोट बैंक और प्रशासनिक जटिलताएं इस राह में बाधा बन रही हैं, इस पर ईमानदार विमर्श जरूरी है।

समाधान का रास्ता केवल आक्रामक भाषणों या भय के नैरेटिव से नहीं निकलेगा। आवश्यकता एक संतुलित, मानवीय और कानूनी दृष्टिकोण की है। सबसे पहले सरकार को पारदर्शी और तथ्य आधारित श्वेत पत्र जारी कर वास्तविक स्थिति देश के सामने रखनी चाहिए। घुसपैठ की अनुमानित संख्या, प्रवेश के प्रमुख मार्ग, फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क और सुरक्षा जोखिमों का समेकित आकलन होना चाहिए। बिना डेटा के नीति केवल अनुमान बनकर रह जाती है।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम सीमा प्रबंधन का आधुनिकीकरण है। स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन निगरानी, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम और तटीय सुरक्षा को एकीकृत करना होगा। स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय बलों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए। जिन क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय दबाव अधिक है, वहां विकास योजनाओं को स्थानीय निवासियों से जोड़कर विश्वास बहाल करना होगा।

अभियान

ऋतु का संगीत और मनुष्य का मन

वसंत पंचमी भारतीय जीवन परंपरा में केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच सदियों से चल रहे संवाद का उत्सव है। माघ की ठंड जब धीरे-धीरे विदा लेने लगती है और धरती पर पीले फूलों की आभा बिखरती है, तब यह पर्व हमारे भीतर भी किसी सोई हुई ऊर्जा को जगा देता है। भारतीय मानस ने ऋतुओं को केवल मौसम के रूप में नहीं देखा, उन्हें जीवन की अवस्थाओं, भावनाओं और संस्कारों से जोड़ा है। वसंत पंचमी उसी दृष्टि का सबसे कोमल और उजला अध्याय है, जहां प्रकृति का रूपांतरण मनुष्य के सांस्कृतिक रूपांतरण में बदल जाता है।

इस दिन का आरंभ ही एक अलग प्रकार की ताजगी से होता है। सुबह की हवा में ठंड के साथ हल्की गर्माहट घुलने लगती है। खेतों में सरसों के फूल मानो धरती पर उतरे छोटे-छोटे सूर्य प्रतीत होते हैं। आम की डालियों पर बौर की खुशबू, कोयल की पहली कूक और आकाश का निर्मल नीलापन मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं, जिसमें मनुष्य स्वतः प्रसन्न हो उठता है। हमारे पूर्वजों ने इस प्राकृतिक बदलाव को केवल देखने भर से संतोष नहीं किया, बल्कि इसे जीवन के उत्सव में बदल दिया। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वह प्रकृति को मंदिर की तरह पूजती है और पर्व की तरह जीती है।

वसंत पंचमी को विद्या और वाणी की देवी सरस्वती से जोड़ने की परंपरा अत्यंत गहरी है। ज्ञान को जीवन के केंद्र में रखने वाली इस सभ्यता ने माना कि सच्चा वसंत मनुष्य के भीतर तब आता है जब उसकी चेतना में प्रकाश का उदय होता है। इसलिए विद्यालयों, घरों और गुरुकुलों में इस दिन सरस्वती पूजन की जाती है। पुस्तकें, कलम, वाद्ययंत्र और रंग-तूलिकाएं पूजा के आसन पर रखी जाती हैं। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रति कृतज्ञता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। बच्चे पहली बार अक्षर लिखते हैं, विद्यार्थी नये संकल्प लेते हैं और कलाकार अपनी साधना को नयी दिशा देने का संकल्प करते हैं।

पीला रंग इस पर्व की आत्मा है। यह रंग केवल वस्त्रों या फूलों तक सीमित नहीं, बल्कि मन की अवस्था का प्रतीक है। पीला रंग सूर्य की ऊर्जा, परिपक्वता और सकारात्मकता का संकेत माना जाता है। जब पूरा समाज इस रंग में रंगता है तो वह सामूहिक आशा का दृश्य बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह रंग मन में उत्साह और स्पष्टता जगाता है। शायद इसी कारण भारतीय परंपरा ने पीले को वसंत का रंग चुना, ताकि बाहरी दृश्य के साथ भीतर का संसार भी आलोकित हो सके।

कृषि प्रधान समाज में वसंत पंचमी का महत्व और गहरा हो जाता है। महीनों की मेहनत के बाद जब रबी की फसल पकने के करीब होती है, तब यह पर्व किसान के मन में भरोसे की किरण बनकर आता है। यह प्रकृति का आश्वासन है कि परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए गांवों में यह दिन केवल पूजा का नहीं, उत्साह और उम्मीद का भी दिन होता है। लोकगीतों में खेत, फूल, मेड़ और पगडंडियां बोलने लगती हैं। मनुष्य और धरती के बीच का रिश्ता किसी कविता की तरह मधुर हो उठता है।

भारत की विविधता इस पर्व में भी दिखाई देती है। अलग-अलग प्रांतों में इसके रूप भिन्न हैं, पर भाव एक ही है। कहीं सरस्वती पूजा की भव्यता है, कहीं पतंगों से भरा आकाश, कहीं संगीत और नृत्य की महफिलें। बंगाल में यह विद्यार्थियों और कलाकारों का सबसे प्रिय दिन है। उत्तर प्रदेश और बिहार में विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। पंजाब और हरियाणा में सरसों के खेतों के बीच लोक उत्सव मनाए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान में पतंगबाजी से आसमान रंगीन हो उठता है। ये सारे रूप मिलकर बताते हैं कि वसंत पंचमी पूरे देश की साझा सांस्कृतिक धरोहर है।

इस पर्व का साहित्यिक और कलात्मक महत्व भी अपार है। संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक, वसंत कवियों का सबसे प्रिय विषय रहा है। कालिदास ने इसे प्रकृति की मुस्कान कहा, भक्त कवियों ने इसे ईश्वर के प्रेम का रूपक बनाया और आधुनिक रचनाकारों ने इसे मनुष्य की आजादी से जोड़ा। शास्त्रीय संगीत में वसंत रागों का विशेष स्थान है। नृत्य में ऋतु आधारित प्रस्तुतियां इस दिन नई ऊर्जा पाती हैं। चित्रकला में पीले, हरे और नीले रंगों का संगम वसंत के सौंदर्य को कैनवास पर उतार देता है। कला के ये सभी रूप बताते हैं कि भारतीय सृजनशीलता की जड़ें प्रकृति में गहराई से धंसी हुई हैं।

खानपान की परंपराएं भी इस उत्सव को मधुर बनाती हैं। केसरिया खीर, मीठे चावल, बूंदी और हलवा केवल व्यंजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक हैं। मिठास जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का संदेश देती है। सामूहिक भोज यह सिखाता है कि आनंद अकेले नहीं, मिलकर सुंदर बनता है। गांवों में आज भी इस दिन लोग एक-दूसरे के घर पकवान भेजते हैं, जो रिश्तों की गर्माहट को जीवित रखता है। भोजन यहां केवल पेट भरने का साधन नहीं, सामाजिक एकता का माध्यम बन जाता है।

वसंत पंचमी का एक सूक्ष्म पक्ष मनोवैज्ञानिक भी है। लंबी सर्दी के बाद मनुष्य के भीतर जो जड़ता आ जाती है, यह पर्व उसे तोड़ता है। रंग, संगीत, सुगंध और सामूहिकता मिलकर मन में नयी उमंग भर देते हैं। आधुनिक जीवन में बढ़ते तनाव और अकेलेपन के बीच ऐसे पर्व मानसिक स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का काम करते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने से भीतर का संतुलन लौटता है। शायद यही कारण है कि प्राचीन समाज ने ऋतु उत्सवों को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया।

आज के समय में इस पर्व का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। तेज रफ्तार शहरी जीवन में मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। स्क्रीन और कंक्रीट के बीच जीते हुए हम धरती की धड़कन भूलने लगे हैं। वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि असली आनंद बाहर की चमक में नहीं, भीतर के संतुलन में है। यह दिन हमें किताबों से दोस्ती करने, संगीत सुनने, पेड़ों के बीच समय बिताने और अपने भीतर झांकने का अवसर देता है।

पर्यावरण के संदर्भ में भी इस पर्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका सहभागी है। फूलों, पक्षियों और नदियों के बिना हमारे उत्सव अधूरे हैं। जब हम सरसों के खेतों को प्रणाम करते हैं, तो दरअसल धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज जब जलवायु संकट गहरा रहा है, वसंत पंचमी हमें सावधान करती है कि यदि हमने प्रकृति का सम्मान खो दिया तो हमारी संस्कृति भी सूख जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में यह पर्व नई प्रेरणा लेकर आता है। स्कूलों में इस दिन कला मेले, पुस्तक प्रदर्शन, संगीत सभाएं और रचनात्मक कार्यशालाएं आयोजित होती हैं। बच्चे समझते हैं कि सीखना केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाना है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध अधिक आत्मीय बनता है। यह परंपरा बताती है कि भारतीय दृष्टि में ज्ञान का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण करना है।

वसंत पंचमी समाज को जोड़ने वाला सेतु भी है। यह लोगों को घरों से बाहर लाकर एक-दूसरे से मिलाता है। ठंड की निष्क्रियता के बाद आया यह पर्व सक्रियता और मेल-मिलाप का वातावरण बनाता है। सामुदायिक कार्यक्रम, गीत-संगीत, खेल और संवाद सामाजिक दूरी को कम करते हैं। ऐसे समय में जब समाज अनेक विभाजनों से जूझ रहा है, यह पर्व एकता की कोमल डोर बन सकता है।

दरअसल वसंत पंचमी जीवन को देखने की एक दृष्टि है। यह सिखाती है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जैसे पेड़ पुरानी पत्तियां गिराकर नयी कोंपलें धारण करते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर की कठोरता छोड़नी चाहिए। ज्ञान वही है जो हमें उदार बनाए, कला वही है जो हमें संवेदनशील करे और धर्म वही है जो हमें प्रकृति से जोड़े। इस पर्व का मूल संदेश यही है कि जीवन में सौंदर्य, विवेक और करुणा का संतुलन बना रहे। जब तक धरती पर फूल खिलते रहेंगे, जब तक बच्चे अक्षर सीखते रहेंगे, जब तक संगीत की धुनें गूंजती रहेंगी, तब तक वसंत पंचमी जीवित रहेगी।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

स्मार्ट शहर के लिए स्मार्ट उपाय : सीसीटीवी + एआई = आवारा गाय को भीड़ में चिह्नित कर उसके मालिक की पहचान उजागर करेगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए राज्य सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गांधीनगर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने के बाद इस टेक्नोलॉजी को राज्य के शासन में समाविष्ट कर नागरिक सेवा वितरण को समृद्ध बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) क्षेत्र के दायरे में आने वाली समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में आवारा पशुओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान आसान बनेगा। अहमदाबाद में भटकती-आवारा गायों के कारण कई बार यातायात समस्या देखने को मिलती है। हाल में अहमदाबाद मनपा की टीम सीसीटीवी कैमरा की सहायता से अलग-अलग क्षेत्रों में आवारा गायों की तसवीर खींचने के बाद उसमें लगी माइक्रो चिप तथा आरएफआईडी टैग के आधार पर गाय को चिह्नित करती है। यह प्रक्रिया मैन्युअल होने के कारण इसमें समय एवं ऊर्जा का काफी व्यय होता है। इस कार्य को तेज बनाने तथा समय एवं ऊर्जा का व्यय घटाने के लिए अब एआई टेक्नोलॉजी को इस कार्य में शामिल करने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

इस समस्या के निवारण के उद्देश्य से गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एक एजेंसी को एआई मॉडल बनाने का कार्य सौंपा गया है। एजेंसी ने डीप लर्निंग मॉडल द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं और उनके आधार पर एजेंसी संचालन समिति के समक्ष उनके द्वारा तैयार किया गया मॉडल शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी। एजेंसी सीसीटीवी कैमरा द्वारा ली जाने वाली तसवीरों को एआई मॉडल के साथ एकीकृत कर रियल टाइम में गाय तथा उसके मालिक की पहचान करने वाला एआई मॉडल तैयार कर रही है।

फिंगर प्रिंट की तरह गाय की नाक है उसकी यूनिक बायोमेट्रिक आईडी : नाक की रचना, आँखों तथा चेहरे को स्कैन करने वाली टेक्नोलॉजी

अहमदाबाद महानगर पालिका के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी, एजेंसी द्वारा एआई मॉडल निर्माण पर कार्य शुरू

गुजरात के शहरों के सर्वांगीण विकास का विजन, एआई टेक्नोलॉजी से स्मार्ट गवर्नेंस की ओर राज्य सरकार के बढ़ते कदम

एजेंसी का प्रस्तावित एआई मॉडल कैसे काम करेगा ?

एजेंसी ने कम्प्यूटर विजन तथा डीप लर्निंग एआई मॉडल द्वारा इस समस्या का समाधान सुझाया है। इस मॉडल अंतर्गत एआई गाय के चेहरे को स्कैन करेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहचान गाय की नाक के आधार पर होगी। जिस प्रकार हर व्यक्ति की फिंगर प्रिंट अलग-अलग होती है, उसी प्रकार हर गाय के नाक का डिजाइन अलग-अलग होता है। इसके अलावा; गाय की आँखों व चेहरे पर कोई दाग या निशान हो, तो उसे भी स्कैन किया जाएगा। उसके आधार पर एआई मॉडल उस गाय को भीड़ में चिह्नित कर लेगा और डेटाबेस के साथ मैच कर गाय के मालिक का विवरण भी प्रस्तुत कर देगा। हाल में अहमदाबाद में लगभग 1 लाख 10 हजार गायों में आरएफआईडी टैग तथा माइक्रो चिप लगी हुई हैं। उसका डेटाबेस अहमदाबाद मनपा द्वारा संरक्षित किया जाता है। शहर में 130 जंक्शन पर कैमरा द्वारा आवारा गायों की तसवीरें ली जाती हैं। एआई आधारित यह सॉल्यूशन यदि कारगर सिद्ध होगा, तो मनपा क्षेत्र में आवारा गायों के कारण होने वाली यातायात व अन्य समस्याओं के शीघ्र निवारण में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से सरकार का आवारा गायों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोककर सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और डेटा आधारित निरीक्षण व्यवस्था को प्रस्थापित करने का उद्देश्य है।

पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली एवं बोरीवली के बीच छठी लाइन का कमीशन किया गया

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सफलतापूर्वक पूर्ण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने मुंबई उपनगरीय खंड में कांदिवली एवं बोरीवली के बीच 3.210 किलोमीटर लंबी छठी लाइन का सफलतापूर्वक कमीशन कर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि 18 जनवरी, 2026 को रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमंडल) द्वारा सफल निरीक्षण के उपरांत प्राप्त हुई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक् प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमंडल) श्री ई. श्रीनिवास ने कांदिवली एवं बोरीवली के बीच नव निर्मित छठी लाइन खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। इसके पश्चात गति परीक्षण किए गए, जिसके बाद इस खंड को नियमित रेल परिचालन के लिए अधिकृत किया गया।

कांदिवली–बोरीवली खंड बांद्रा टर्मिनस एवं बोरीवली के बीच परियोजना के फेज-I का अंतिम हिस्सा है। इससे पूर्व खार रोड–गोरेगांव खंड का कमीशन नवंबर 2023 में तथा गोरेगांव–कांदिवली खंड का कमीशन अक्टूबर 2024 में किया जा चुका है। अंतिम खंड का कार्य 18 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 के बीच मात्र 30 दिनों की सुव्यवस्थित समय-सीमा में पूर्ण किया गया, जो पश्चिम रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर पूलानिंग, चौबीसों घंटे कार्य निष्पादन एवं

उत्कृष्ट समन्वय को दर्शाता है।

इस कमीशनिंग कार्य में बड़े पैमाने पर ट्रैक पुनर्संरेखण, पुलों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिक सिगनलिंग का एकीकरण, विद्युतीकरण कार्य, भूमि अधिग्रहण आदि शामिल थे। उपनगरीय यात्रियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने और साथ ही उच्चस्तर की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकांश कार्य रात्रि ब्लॉक अवधि के दौरान किए गए।

श्री विनीत ने आगे बताया कि यह क्षमता वृद्धि उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन को अधिक प्रभावी रूप से अलग करने में सक्षम बनाती है, जिससे परिचालन सुचारू रूप से होगी, कंजेशन कम होगी तथा समयपालनता में सुधार होगा। इस अतिरिक्त लाइन से मेंटेनेंस ब्लॉक और पिक ट्रैफिक अवधि के दौरान परिचालन क्षमता भी सुदृढ़ होगी, जिससे मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में सेवा की विश्वसनीयता और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी।

इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संपर्क को अत्यंत सीमित समय-सीमा में पूरा किया जाना पश्चिम रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता, परियोजना प्रबंधन में अनुशासन तथा यात्री-केंद्रित विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह परियोजना ट्रेनों के सुचारु परिचालन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगी और प्रतिदिन यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगी।

पश्चिम रेलवे निरंतर बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा विश्वसनीय, कुशल और यात्री-केंद्रित रेल सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे मुंबई की जीवनरेखा के रूप में उसकी भूमिका और अधिक सुदृढ़ होती है।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने टिकट जांच में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 कर्मचारियों को किया सम्मानित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में टिकट जांच के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

इस संबंध में भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भावनगर मंडल के टिकट जांच कर्मी अत्यंत जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये कर्मी न केवल यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने में सहायक हैं, बल्कि रेलवे की आय वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि भावनगर मंडल द्वारा अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5.09 करोड़ की आय अर्जित की गई है, जबकि मात्र अप्रैल 2025 माह में ही 77.23 लाख की आय दर्ज की

गई है।

मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सम्मानित किए गए कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं– श्री आई. बी. मुंशी (आरक्षण पर्यवेक्षक, गांधीग्राम), श्री ध्रुव अमीन (सीनियर सीसी/टीसी, गांधीग्राम), श्री योगेन्द्र सिंह (सीसी/टीसी, जूनागढ़), श्री आर. एम. चौहान (मुख्य वाणिज्य लिपिक, भावनगर), श्री वी. एन. जडेजा (आरक्षण पर्यवेक्षक, जूनागढ़), श्री शैलेष बी. परमार (उप मुख्य टिकट निरीक्षक, गांधीग्राम), श्री अरविंद कुमार गुर्जर (उप मुख्य टिकट निरीक्षक, वेरावल), श्री के. सी. मीणा (मुख्य टिकट निरीक्षक, गांधीग्राम), श्री प्रेम चंद (सीनियर सीसी/टीसी, गांधीग्राम), श्री राजन कुमार सिंह (मुख्य टिकट निरीक्षक, वेरावल), श्री आर. पी. मेघवंशी (मुख्य टिकट संग्राहक, बोटाद), श्री जे. पी. मकवाना (मुख्य टिकट निरीक्षक, बोटाद) एवं श्री अमोद कुमार (सीसी/टीसी, बोटाद)।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी सम्मानित कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

77वें गणतंत्र पर्व 26 जनवरी, 2026 का राज्य स्तरीय समारोह नवगठित वाव-थराद जिले में आयोजित होगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : 77वें गणतंत्र पर्व 26 जनवरी 2026 का राज्य स्तरीय समारोह नवगठित वाव-थराद जिले में आयोजित होगा।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वाव-थराद जिला मुख्यालय मालपुर में नए कोर्ट के सामने स्थित हेलीपैड मैदान में गणतंत्र पर्व पर सुबह 9 बजे राष्ट्रध्वज फहरा कर ध्वज वंदन कराएंगे और परेड मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुलिस बल द्वारा विभिन्न निदर्शन भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से राष्ट्रीय पर्वों का राज्य स्तरीय समारोह अलग-अलग जिलों में जन भागीदारी से आयोजित करने की शुरू कराई गई नूतन परंपरा के अनुसार 77वें गणतंत्र पर्व का राज्य स्तरीय समारोह नवगठित वाव-थराद जिले में आयोजित होने वाला है।

यह राष्ट्रीय पर्व राज्य के विभिन्न जिलों में तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होगा। इसमें उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी अहमदाबाद में मकरबा क्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा; राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य सम्बद्ध जिलों के मुख्यालयों पर गणतंत्र पर्व समारोह में उपस्थित रहकर ध्वजारोहण करेंगे।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा इस संदर्भ में घोषित की गई सूची के अनुसार केबिनेट स्तरीय मंत्रियों में वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई नवसारी जिले के चीखली में, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी राजकोट जिले के जेतपुर में, ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल गांधीनगर जिले के माणसा में, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया पोरबंदर जिले के राणावाव में, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल वलसाड जिले के उमरगाम में, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया दाहोद जिले के गोविंद गुरु-लींबडी में, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा साबरकाँठा जिले के हिंमतनगर में तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी खेडा जिले के ठासरा में तिरंगा फहराएंगे।

राज्य स्तरीय मंत्री जिन जिलों में गणतंत्र पर्व के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण करेंगे; उनमें जल संसाधन राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल नर्मदा जिले के एकतानगर (केवडिया) में, महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील छोटा उदेपुर जिले के बोडेली में, मत्स्योद्योग राज्य मंत्री श्री परसोत्तम सोलंकी गीर-सोमनाथ जिले के तालाला में, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री कांतिभाई अमृतिया कच्छ जिले के भुज में, कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा पंचमहाल जिले के हालोल में, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला सुरेन्द्रनगर जिले के वढवाण में, विधि राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया भावनगर जिले के वलभीपुर में, परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी मेहसाणा जिले के विसनगर में, खेल राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित डांग जिले के आहवा में, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांग अमरेली जिले के खांभा में, वित्त राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल वडोदरा जिले के वाघोडिया में, राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा आणंद जिले के खंभात में, आदिजाति विकास राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा महिसागर जिले के कडाणा में, कुटीर उद्योग राज्य मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर पाटण जिले के शंखेश्वर में तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा बोटाद जिले के गढडा में तिरंगा फहराएंगे।

राज्य के जिन 9 जिलों के तहसील मुख्यालयों पर जिला कलेक्टरों द्वारा ध्वजारोहण होने वाला है; उनमें अरवल्ली जिले के मेघरज में, बनासकाँठा के ओगड में, भरूच जिले के आमोद में, देवभूमि द्वारका जिले के भाणवड में, जामनगर जिले के कालावड में, जूनागढ जिले के केशोद में, मोरबी जिले के टंकारा में, सूरत जिले के मांडवी में तथा तापी जिले के उच्छल में सम्बद्ध जिला कलेक्टर तिरंगा झंडा फहराएंगे।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में ध्वजारोहण करेंगे तथा परेड की सलामी लेंगे

उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य राज्य के जिलों में विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर फहराएंगे तिरंगा

9 जिलों में

कांदिवली कार शेड में प्रवेश एवं निकास के निलंबन के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त

(जीएनएस)। कांदिवली कार शेड में प्रवेश एवं निकास के निलंबन तथा कांदिवली–मालाड के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइन पर लगाए गए गति प्रतिबंधों के कारण 20 जनवरी, 2026 को कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। ब्लॉक के कारण प्रभावित उपनगरीय ट्रेनों की सूची अनुलग्नक–I में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित उपनगरीय स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों पर ध्यान में रखें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

वडोदरा स्टेशन पर रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर को बनाया गया बेहतर, प्लेटफार्म का भी किया गया विस्तार

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वडोदरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ राइडिंग क्वालिटी को बेहतर बनाने के क्रम में इंफ्रा के कई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए है। इसके साथ साथ वडोदरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को 50 मीटर तक विस्तारित भी कर दिया गया है, जिससे ट्रेनों के ऑपरेशन में सुविधा के साथ साथ प्लेटफार्म पर यात्रियों का मूवमेंट और बेहतर हो सकेगा। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वडोदरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के इंफ्रा के कई महत्वपूर्ण कार्यों को इंजीनियरिंग विभाग के रेलकर्मियों ने अथक प्रयास से महज 25 दिन ब्लॉक लेकर पूर्ण कर लिया। पहले प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन पर लगातार पानी रुक रहा था, जिससे गंदगी फैल रही थी और बार-बार ट्रैक सर्किट फेल हो रहे थे। जिसकी वजह से ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पर असर पड़ रहा था। लंबे समय तक ट्रैक पर पानी जमा रहने से रेल ट्रैक के स्लीपर और ट्रैक की बनावट खराब हो रही थी, जिससे ट्रेन परिचालन में संरक्षा प्रभावित हो रही थी। इन कमियों को ठीक करने के लिए वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 400 मीटर

लंबी नई वॉटर हाइड्रेंट पाइपलाइन बिछाई गई। सतह और ज़मीन के नीचे के पानी को प्रभावी ढंग से निकालने के लिए लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के बीच 300 मीटर का एक नया सेंट्रल ड्रेन बनाया गया। इसके अलावा, मौजूदा 380 मीटर सेंट्रल ड्रेन की मरम्मत कर उसे ठीक किया गया है, और उस पर कवर स्क्रीन भी लगाई गई।

इसके अतिरिक्त, सही गिट्टी कुशन को बहाल करने, ड्रेनेज को बेहतर बनाने और खराब गिट्टी को हटाने के लिए लाइन नंबर 3 पर 790 मीटर की डीप स्क्रीनिंग की गई। क्षतिग्रस्त और खराब स्लीपरों को बदलने और ट्रैक की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 790 मीटर का टोटल स्लीपर रिन्यूअल (TSR) किया गया।

सेक्शन को 30 किमी प्रति घंटे की अनुमत गति के लिए उपयुक्त बनाने के लिए ट्रैक ज्योमेट्री को ठीक किया गया है, जिसमें अलाइनमेंट, कैंट और गेज शामिल हैं और कर्व पैरामीटर को फिर से अलाइन किया गया है। इन इंफ्रा कार्यों से प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ राइडिंग क्वालिटी भी बेहतर होगी।

सोना वायदा 1.45 लाख रुपये और चांदी वायदा 3.04 लाख रुपये के नए शिखर पर: क्रूड ऑयल वायदा 63 रुपये फिसला

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 244270.04 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 56746.91 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 187508.13 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 39812 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4441.5 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 46765.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 143321 रुपये के भाव पर खूलकर, 145500 रुपये के ऑल टाइम हाई और 143320 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 142517 रुपये के पिछले बंद के सामने 2379 रुपये या 1.67 फीसदी की मजबूती के साथ 144896 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 1402 रुपये या 1.21 फीसदी की तेजी के संग 117210 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 203 रुपये या 1.4 फीसदी की तेजी के संग 14694 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 142680 रुपये के भाव पर खूलकर, 144895 रुपये के दिन के उच्च और 142680 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 2280 रुपये या 1.6 फीसदी की तेजी के संग 144552 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 143879 रुपये के भाव पर खूलकर, 145189 रुपये के दिन के उच्च और 143300 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 142913 रुपये के पिछले बंद के सामने 1802 रुपये या 1.26 फीसदी की तेजी के संग 144715 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 293100 रुपये के भाव पर खूलकर, 304200 रुपये के ऑल टाइम हाई और 293100 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 287762 रुपये के पिछले बंद के सामने 14918 रुपये या 5.18 फीसदी की बढ़त के साथ 302680 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 14547 रुपये या 5.02 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 304594 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 14579 रुपये या 5.03 फीसदी की तेजी के संग 304671 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 4677.70 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 9 रुपये या 0.7 फीसदी की तेजी के संग 1298.5 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.38 फीसदी बढ़कर 314 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.65 रुपये या 0.52 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 318.15 रुपये प्रति किलो पर

आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 50 पैसे या 0.26 फीसदी चढ़कर 191.9 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5299.48 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5423 रुपये के भाव पर खूलकर, 5435 रुपये के दिन के उच्च और 5351 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 63 रुपये या 1.16 फीसदी गिरकर 5386 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 60 रुपये या 1.1 फीसदी गिरकर 5388 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 283.7 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 322.3 रुपये और नीचे में 283.6 रुपये पर पहुंचकर, 280.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 37.3 रुपये या 13.3 फीसदी की तेजी के संग 317.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 37.2 रुपये या 13.26 फीसदी की तेजी के संग 317.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 973 रुपये पर खूलकर, 50 पैसे या 0.05 फीसदी की नरमी के साथ 975 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 21515.48 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 25249.98 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3845.95 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 273.89 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 66.49 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 471.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 577.98 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 4704.95 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.77 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.19 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20476 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 78121 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26473 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 383183 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 44463 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14129 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38608 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 100614 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17062 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 41259 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 39610 पॉइंट पर खूलकर, 39939 के उच्च और 39102 के नीचले स्तर को छूकर, 1172 पॉइंट बढ़कर 39812 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 43.8 रुपये की गिरावट के साथ 226 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 11.1 रुपये की बढ़त के साथ 13.7 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 760 रुपये की बढ़त के साथ 1736.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6913 रुपये की बढ़त के साथ 15823.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 67 पैसे की नरमी के साथ 17.85 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 37 पैसे की नरमी के साथ 1.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 19 रुपये की बढ़त के साथ 245.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 23.3 रुपये की गिरावट के साथ 10.15 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 527 रुपये की गिरावट के साथ 346.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 8592.5 रुपये की गिरावट के साथ 12900 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 9.44 रुपये की गिरावट के साथ 19.1 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 33 पैसे की नरमी के साथ 0.5 रुपये हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 56746.91 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 187508.13 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 46765.46 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39812 पॉइंट के स्तर पर

आत्मनिर्भर गुजरात के निर्माण में साप्ति की उल्लेखनीय भूमिका दिसंबर-2025 तक संस्थान से 674 उम्मीदवार स्नातक हुए

▸▸ 'साप्ति' के माध्यम से ध्रांगध्रा के युवक अक्षय पिलाणी बने शिल्पकला में पारंगत, प्रतिमाह करते हैं 40,000 रुपए की कमाई

▸▸ शिल्पकला क्षेत्र में कौशल विकास को वेग दे रहा है स्टोन आर्टिजन पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (साप्ति)

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र का अनुकरण करते हुए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित स्टोन आर्टिजन पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी 'एसएपीटीआई/साप्ति' राज्य के पत्थर शिल्पकला क्षेत्र में कौशल विकास को वेग दे रहा है। यह संस्थान पत्थर कला की मूल्यवान विरासत को बनाए रखने के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। दिसंबर-2025 तक कुल 674 उम्मीदवार इस संस्थान से स्नातक हुए हैं।

गुजरात में अंबाजी तथा ध्रांगध्रा में हैं आर्टिजन पार्क

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार के खान एवं उद्योग विभाग तथा भूविज्ञान एवं खनन कार्य आयुक्त कार्यालय-गांधीनगर द्वारा स्थापित साप्ति राज्य के शिल्पकला उद्योग की संभावनाओं का उपयोग करता है और पत्थर कला तथा शिल्प-स्थापत्य की मूल्यवान विरासत को आगे बढ़ा रहा है। राज्य में अंबाजी (बनासकाँठा जिला) और ध्रांगध्रा (सुरेन्द्रनगर जिला) में – दो आर्टिजन पार्क्स की स्थापना की गई है। उत्तर गुजरात में स्थित साप्ति-अंबाजी संगमरमर के शिल्पों पर ध्यान केन्द्रित करता है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित साप्ति-ध्रांगध्रा रेत-पत्थर के शिल्पों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में आज साप्ति जैसा संस्थान सांस्कृतिक धरोहर को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

2022 से 2025 के दौरान साप्ति के दोनों केन्द्रों पर 1,082 उम्मीदवारों का पंजीकरण हुआ

2022 से 2025 के दौरान साप्ति के दोनों केन्द्रों पर 1,082 उम्मीदवारों का पंजीकरण हुआ है। 26 दिसंबर, 2025 तक कुल 674 उम्मीदवार इस संस्थान से स्नातक हुए हैं, जिनमें अंबाजी केन्द्र के 307 उम्मीदवार तथा ध्रांगध्रा केन्द्र के 367 उम्मीदवार शामिल हैं। ये आँकड़े गुजरात के शिल्प उद्योग के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण करने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाते हैं।

साप्ति के माध्यम से ध्रांगध्रा के युवक अक्षय पिलाणी बने शिल्पकला में पारंग, प्रतिमाह करते हैं 40,000 रुपए की कमाई

सुरेन्द्रनगर जिले की ध्रांगध्रा तहसील के चुली गाँव के युवक अक्षय पिलाणी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद भारतीय पुलिस या सेना में जुड़ना चाहते थे। इस बीच उन्हें साप्ति-ध्रांगध्रा के माध्यम से पत्थर हस्तकला तथा डिजाइन में कॅरियर के अवसर के बारे में जानने को मिला। स्टोन क्राफ्ट तथा डिजाइन कोर्स में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उनके कॅरियर को नया मोड़ मिला। ढाँचागत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से अक्षय ने पत्थर की नक्काशी/उत्कीर्णन कला, चित्रकारी, प्रोडक्ट डिजाइन तथा आधुनिक मशीनरी के उपयोग के साथ परंपरागत उत्कीर्णन कला की तकनीक में भी निपुणता प्राप्त की। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के अतिरिक्त; उन्होंने सम्बद्ध उद्योग के व्यवसायियों के साथ काम करके व्यावहारिक अनुभव तो प्राप्त किया ही, साथ ही वित्तीय सहायता भी प्राप्त की। किसान परिवार से आने वाले अक्षय पिलाणी ने आज एक विशेषज्ञ कारीगर के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। उन्होंने चंडीगढ़ में दो बड़े स्टोन कार्विंग (पत्थर पर उत्कीर्णन) प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आज वे हर महीने लगभग 40,000 रुपए कमाते हैं। उनकी इस यात्रा ने अन्य युवाओं को भी शिल्पकला के प्रति आकर्षित किया है।

सदियों पुरानी शिल्पकला को बनाए रखने में साप्ति की उल्लेखनीय भूमिका

साप्ति का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, नवीनता तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन देते हुए देश की शिल्पकला को मजबूत बनाकर उसका जतन करना है। रोजगार सृजन के अलावा; साप्ति गुजरात की सदियों पुरानी पत्थर कला एवं स्थापत्य की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंपरागत तकनीकों, आधुनिक संसाधनों और वैश्विक डिजाइन के समन्वय के साथ यह संस्थान शिल्पकला की विरासत को पुनर्जीवित करने के साथ उसे आधुनिक बाजारों के अनुकूल बना रहा है।

आईएमएफ का भरोसा: भारत की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साहजनक खबर सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधन अक्टूबर में जताए गए पूर्व अनुमान से 0.7 प्रतिशत अधिक है और दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आईएमएफ की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश धीमी वृद्धि और महंगाई के दबाव से जूझ रहे हैं। वाशिंगटन स्थित आईएमएफ द्वारा जारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत का आर्थिक प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा। उपभोक्ता मांग में तेजी, बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च और सेवा क्षेत्र में आई मजबूती ने विकास को गति दी है। रिपोर्ट के अनुसार चौथी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधियों के सशक्त बने रहने की संभावना है, जिसके कारण पूरे वर्ष के अनुमान में सकारात्मक संशोधन किया गया। इससे पहले आईएमएफ ने भारत के लिए 6.6 प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान जताया था, जिसे अब उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है।

आईएमएफ का आकलन केवल चालू वर्ष तक सीमित नहीं है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी वृद्धि दर का अनुमान 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की घरेलू मांग, निवेश माहौल और डिजिटलीकरण की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को सहारा देती रहेगी। हालांकि संस्था ने यह भी संकेत दिया है कि 2027-28 के आसपास विकास की गति में कुछ नरमी आ सकती है, क्योंकि अस्थायी और चक्रीय कारकों का असर धीरे-धीरे कम होगा।

सरकारी आंकड़े भी आईएमएफ के इस सकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में यह बढ़कर 8.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान में पूरे वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई है। तुलना के तौर पर वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही थी, जो बताती है कि देश अब तेज रफ्तार विकास की राह पर लौट आया है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विनिर्माण क्षेत्र में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने भारत को वैश्विक मंदी के असर से काफी हद तक बचाए रखा है। ग्रामीण मांग में सुधार और रोजगार के नए अवसर भी विकास को सहारा दे रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों की भी सराहना की गई है, जिनके कारण महंगाई नियंत्रण में रही और वित्तीय स्थिरता बनी रही।

विशेषज्ञों के अनुसार यह अनुमान केवल आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि भारत की नीतिगत विश्वसनीयता पर अंतरराष्ट्रीय मुहर है। वैश्विक निवेशक भारत को अब एक स्थिर और भरोसेमंद बाजार के रूप में देख रहे हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। आईएमएफ का यह भरोसा आने वाले समय में विदेशी निवेश को और प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे रोजगार सृजन और आय वृद्धि को नई ताकत मिलेगी।

कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह आकलन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत संदेश लेकर आया है। दुनिया जहां आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, वहीं भारत विकास के प्रमुख इंजन के रूप में उभरता दिख रहा है। आने वाले वर्षों में यदि नीतिगत निरंतरता और सुधारों की गति बनी रही तो देश न केवल इन अनुमानों को हासिल करेगा, बल्कि उनसे आगे निकलने की क्षमता भी रखता है।

एमएसएमई को बड़ी राहत: सरकारी बैंकों ने 52,300 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सरकारी बैंकों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने डिजिटल ऋण मूल्यांकन प्रणाली के तहत लगभग 3.96 लाख एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनकी कुल राशि 52,300 करोड़ रुपये से अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय पहुँच को आसान बनाने में बैंकिंग प्रणाली कितनी सक्रिय और तेज़ हो गई है। सरकारी बैंकों की यह सफलता डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (Credit Assessment Model - CAM) का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसे वर्ष 2025 में लागू किया गया था। इस प्रणाली के तहत उद्यमियों की डिजिटल गतिविधियों, दस्तावेज़ी प्रमाणों और वित्तीय डेटा के आधार पर ऋण पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। इससे न केवल ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया तेज़ हुई, बल्कि निर्णय अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष भी बन गया।

क्रेडिट असेसमेंट मॉडल के माध्यम से आवेदनकर्ताओं की डिजिटल पहचान, केवाईसी प्रमाणीकरण, मोबाइल और ई-मेल सत्यापन, जीएसटी और बैंक स्टेटमेंट के डेटा विश्लेषण, आयकर रिटर्न और क्रेडिट सूचना कंपनियों के आंकड़ों की जांच की जाती है। साथ ही, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट्स का भी उपयोग किया जाता है। इसके कारण किसी भी एमएसएमई उद्यमी को बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे 24 घंटे, वर्ष के किसी भी दिन, कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ डिजिटल रूप से अपलोड कर सकते हैं। ऋण स्वीकृति के समय भौतिक दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

डिजिटल प्रणाली की वजह से ऋण आवेदन प्रक्रिया अब पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज़ और सरल हो गई है। आवेदनकर्ता को निर्णय की जानकारी तुरंत ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती है, जिससे समय की बचत होती है और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में तेजी आएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल ऋण मूल्यांकन प्रणाली एमएसएमई उद्यमियों के लिए भरोसे और विश्वास को भी मजबूत करेगी। पारदर्शी और त्वरित ऋण प्रक्रिया से छोटे व्यवसायों की योजनाएं समय पर पूरी होंगी, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा, इस प्रणाली से वित्तीय समावेशन में भी सुधार हुआ है, क्योंकि छोटे और नए उद्यमियों को अब बड़ी आसानी से क्रेडिट तक पहुँच मिल रही है।

सरकार की यह डिजिटल पहल न केवल एमएसएमई को सशक्त बनाएगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने में भी योगदान देगी। आने वाले वर्षों में जैसे-जैसे डिजिटल ऋण प्रणाली और परिष्कृत होगी, इसके माध्यम से और अधिक उद्यमियों को ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश में व्यवसाय और निवेश का माहौल और भी सशक्त होगा। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास और नवाचार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

आसमान तले बिताई रात, पालकी पर किया दंड तर्पण शंकराचार्य ने माघ मेला प्रशासन पर उठाए सवाल

(जीएनएस)। प्रयागराज। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान रोके जाने की घटना पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि पतित पावनी मां गंगा की संतान होने के नाते किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन के व्यवहार को अनुचित और धार्मिक अधिकारों का हनन बताया।

घटना के विरोध स्वरूप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शिविर के बाहर ही पालकी पर विराजमान रहे और सोमवार सुबह दंड, तर्पण एवं पूजा अर्चना की। उन्होंने बिना अन्न और जल के पूरी रात पालकी पर बिताई। उनके प्रवक्ता शैलेंद्र योगी सरकार ने बताया कि भक्तों और शिष्यों ने संगम की रेती पर रात बिताई और राम, श्रीराम, जय सियाराम के जाप के साथ शंकराचार्य की पूजा अर्चना में शामिल रहे।

शंकराचार्य ने मेला प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्नान कार्यक्रम की पूर्व सूचना दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने अनुमति न लेने का हवाला दिया और उन्हें पीपा पुल नंबर-2 पर रोक लिया। इस दौरान संतों के साथ दुर्व्यवहार,

गाली-गलौज और मारपीट की गई, जिसमें 15 से अधिक लोग घायल हुए।

उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माइक के माध्यम से बार-बार यह घोषणा करवाई गई कि वे मां गंगा के खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने प्रदेश के गृह सचिव मोहित गुप्ता, प्रयागराज मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने घटना को लेकर भ्रामक जानकारी भी सार्वजनिक की।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि घटना के दौरान उनकी जान को खतरा हो सकता था। सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि वे किसी धरने पर नहीं बैठे हैं, लेकिन जब तक प्रदेश के मुखिया स्वयं आकर माफी नहीं मांगते और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बारे में शंकराचार्य ने सवाल उठाया कि मौनी अमावस्या का स्नान शांतिपूर्ण और सफल बताया गया, जबकि उनके और संतों के साथ जो व्यवहार हुआ, वह क्यों दिखाई नहीं दिया। इस घटना ने माघ मेला प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं और धार्मिक स्वतंत्रता के सम्मान की मांग को बढ़ा दिया है।

गुजरात में भाजपा को हराने की जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की: अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना

(जीएनएस)। वडोदरा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वडोदरा में बूथ वालंटियर्स के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भाजपा जाएगी और गुजरात की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथ में आएगी। पिछले 30 वर्षों से भाजपा डर, जेल और भ्रष्टाचार के सहारे शासन कर रही है, लेकिन अब लोगों के मन से उनका डर खत्म हो गया है।

केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं और इसलिए जनता उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल आम आदमी पार्टी ही गुजरात में भाजपा को हरा सकती है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रदेश को लूट लिया है और अब यह सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि गुजरातियों के सम्मान और न्याय की लड़ाई बन गई है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का संगठन गुजरात में तेजी से विस्तार कर रहा है और अब भाजपा का संगठन इस स्तर पर नहीं है। भाजपा ने पूरे राज्य में भय और अत्याचार फैलाया, जिससे लोग परेशान हो चुके हैं। हालांकि अब जनता डर को पीछे छोड़ रही है और खुले तौर पर भाजपा के खिलाफ खड़े हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 30 सालों में केवल भय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के सहारे गुजरात पर शासन किया है।

केजरीवाल ने जेल में बंद पार्टी नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रवीण राम और राजू करपड़ा समेत कई नेता पिछले तीन महीने से जेल में हैं। भाजपा सरकार ने किसान आंदोलन को दबाने के लिए 85 गरीब किसानों को जेल में डाल दिया, जबकि यह आंदोलन शांतिपूर्ण था। उन्होंने कहा कि किसानों के परिवारों ने समर्थन दिया है और यदि जरूरत पड़ी तो उनके बच्चे तीन साल भी जेल में रहने को तैयार हैं। केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने गुजरात के संसाधनों को लूट लिया, किसानों के खाद-बीज और पानी पर कब्जा किया, फसलों के सही दाम नहीं दिए, सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पताल नष्ट किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी भाजपा को हरा नहीं सकती, क्योंकि वे भाजपा के साथ मिलकर अपने धंधे चला रही हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा से ठेके नहीं लेती और सिर्फ जनता के लिए काम करती है।

उन्होंने कहा कि वडोदरा के भाजपा के पांच विधायक—शैलेश मेहता, केतन इनामदार, धर्मेंद्र सिंह बघेला, अक्षय पटेल और चैतन्य सिंह झाला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में भारी गिरावट की ओर इशारा किया। सामान्य नागरिक के लिए सरकारी काम करवाना युद्ध जैसा बन गया है।

अरविंद केजरीवाल का यह भाषण साफ संकेत है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भाजपा को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है और कांग्रेस से ज्यादा जनता का विश्वास उन्हें है।

भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊर्जा, पीयूष गोयल ने अमेरिकी सीनेटर और राजदूत से की महत्वपूर्ण बातचीत

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर स्टीव डेन्स और भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर से शिष्टाचार भेंट की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देना और साझा हितों पर आधारित सहयोग को और सुदृढ़ करना था। बैठक में व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भविष्य की सहयोग संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका साझेदारी को लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी हितों के आधार पर मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया गया कि आपसी संवाद और उच्चस्तरीय समन्वय से आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स और राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि यह संवाद दोनों देशों के बीच सार्थक और दूरदर्शी विचारों के आदान-प्रदान का अवसर रहा, जो आपसी सहयोग को और बढ़ावा देगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रविवार को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स से भेंट की थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों की व्यापक समीक्षा करते हुए रणनीतिक, कूटनीतिक और वैश्विक महत्व पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी सीनेटर डेन्स से मुलाकात कर द्विपक्षीय रिश्तों को और सुदृढ़ करने के मुद्दों पर चर्चा की थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रही ये उच्चस्तरीय बैठकें भारत-अमेरिका साझेदारी की बढ़ती सक्रियता और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हैं। इन संवादों से व्यापार, निवेश और वैश्विक मंचों पर दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा और मजबूती मिलेगी, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रूप से लाभ होगा।